10 दिसम्बर 2013

जेपीसी के जरिये करतूतों पर पर्दा, प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी

अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

दूरसंचार और स्पेक्ट्रम आवंटित करने और उसकी कीमत तय करने के मामले की जांच के लिए संसद ने एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की थी। मामूली बहुमत से मंजूर जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्य सभा में पेश की गई। कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार के आचरण से स्पष्ट हो गया है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों से उन्होंने सबक नहीं सीखा है। उनकी कोशिश रहती है, पहले तो तरह–तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ और फिर उन्हें छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दो।

जिन प्रमुख मुद्दों की जेपीसी को जांच करनी है, वे हैं –

(1) क्या 2008 में आवंटित स्पैक्ट्रम 2001की कीमतों पर दिये जा सकते थे?

(2) क्या जिस प्रक्रिया से स्पैक्ट्रम आवंटित किये जाने थे उसके संबंध में गोल पोस्ट बदला जा सकता था।

(3) क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को तत्कालीन दूरसंचार मंत्री द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी थी और उन्होंने इस भेद को छिपाया?

इनमें से अधिकतर मुद्दों की अधिकांश रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है। इसके विपरीत रिपोर्ट के अधिकांश हिस्से में एनडीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया है। निश्चित तौर पर रिपोर्ट विश्वास करने योग्य नहीं है। जेपीसी ने बोफोर्स मामले की भी जांच की थी लेकिन उसने अनुमान लगा लिया कि बिचौलियों को दी गई दलाली रिश्वत नहीं थी बल्कि निपटारा शुल्क थे। सीबीआई के आरोपपत्र में इस परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया। नोट के बदले वोट घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति ने विपक्षी सांसदों पर दोष मढ़ दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि वे व्हीसल ब्लोअर थे और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि संसदीय संस्थानों की गरिमा बनी रहे तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सच्चाई सामने आए और उसे छिपाया नहीं जाए।

विपक्षी सांसदों ने दूरसंचार जेपीसी के अध्यक्ष को जो असहमति पत्र दिया उसे संशोधित कर दिया गया है। आज, मैंने राज्य सभा में एक मुद्दा उठाया, क्या समिति के अध्यक्ष असहमति पत्र में व्यक्त केवल अनावश्यक या असंसदीय संदर्भों को संपादित कर सकते हैं या वे असहमति पत्र के सार में बदलाव कर सकते हैं जिसे प्रस्तुत किया गया है? ऐसा करके अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन किया है। मैं इस मुद्दे पर सभापति का निर्णय चाहता था? खेद की बात है कोई निर्णय नहीं आया।

मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि सरकार के कदम की पोल खुल गई है। राजा नंगा है। जेपीसी के जरिये करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश शर्मिंदगी से नहीं बचा सकती।

.....